amount of grants given to TIFR, for development of solid state microwave diodes, Rs. 3.22 lakhs in 1973-74 and to BEL, Rs. 10 lakhs in 1973-74. As far as I know—I will check on this point—grants have not been given to other institutions prior to this. But so far as the future is concerned, development work at Pilani, as I have mentioned in my main reply, will cover a four-year period and involve an outlay of Rs. 67.5 lakhs by the Council of Scientific and Industrial Research and 765,000 dollars to be made available under the UNDP.

SHRI BABUBHAI M. CHINAI: I would like to know from the hon. Minister whether it is a fact that 25 to 30 per cent of the silicon semi-conductor devices are foreign components and if they are manufactured locally and substituted, then we would incur foreign exchange of only eight per cent of the total cost. Also we have been told that we are importing pellets worth Rs. 2 crores. Is it not a fact that if we import a little more of pellets and house them, there will be a greater export potential and we will be able to earn more foreign exchange?

SHRI K. C. PANT: Sir, certain exports are already being made. These are of the order of Rs. 12 lakhs in 1972-73 and 1973-74 from the CDIL, and Rs. 1.5 lakhs in 1972-73 and Rs. 4.62 lakhs in 1973-74 from Hindustan Conductors . Then with respect of export of semi-conductor devices, he has made certain suggestions for import substitution and for increasing exports. These I shall get examined.

MR. CHAIRMAN: Next question.

Utilization of Rain water for Irrigation

*93. SHRI NAGESHWAR PRASAD SHAHI.
SHRI JAGDISH JOSHI:
SHRI GUNANAND THAKUR:

Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state:

(a) how much rain water is utilised for agricultural purposes in the country and how much of it goes waste;

(b) whether there is any plan under Government's consideration to evolve ways and means for utilizing maximum rain water for irrigation purposes; and

(c) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (SHRI K. C. PANT): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The average annual rainfall in the country amounts to 3440 thousand million cubic metres of which 1881 thousand million cu.m. appears as surface run-off. The utilisable surface run-off is estimated as 666 thousand million cu.m. while the utilisable ground water potential has been estimated as 204 thousand million cu.m, thus the total utilisable water is 870 thousand million cu.m. At the end of 1973-74, it was estimated that 241 thousand million cu.m. of surface water and 96 thousand million cu.m. of ground water were being utilised for the purposes of irrigation.

(b) and (c) Some of the important steps being taken for maximising the utilisation of rain water are:

(i) Expediting the pace of development of irrigation by implementation of larger programmes of major, medium and minor irrigation schemes;

(ii) Integrated use of surface and ground water in the command of irrigation projects.

(iii) Programme of Command Area Development to ensure optimum utilisation of irrigation potential created.

(iv) Modernisation of existing canal systems.

श्री जगदीश जोशी : सभापति महोदय, क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि 2 लाख 41 हजार घन फुट पानी, जिसके उपयोग की उम्मीद लगाई है, उसमें नदियों एवम् प्राकृतिक स्रोतों का जल कितना प्रतिशत है ?

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Jagdish Joshi.

श्री के० सी० पन्त : इसमें यह दिया गया है कि···

श्री जगदीश जोशी : जो युटिलाइज किया जा रहा है उसमें रिवर वाटर युटिलाइज किया है। एक तो रिवर का पानी है और एक रनिंग वाटर है। तो रनिंग वाटर अलग है। रिवर वाटर ओरिजिनल कितना है, रनिंग वाटर कितना है?

श्री के० सी० पन्त : यह तो, अखीर में, चाहे वर्फ से पानी आता हो या वारिश से पानी आता हो, पानी का स्रोत तो वही है। (*Interruption*) वर्फ का भी वहीं से आता है रेन्फाल का भी वही से आता है। वर्फ तो एक फार्म है रेन्फाल का तो इसमें मैं तो समझा नहीं। स्टेटमेंट में साफ साफ दिया है कि :

"At the end of 1973-74, it was estimated that 241 thousand million cubic metres of surface water were being utilised for purpose of irrigation."

श्री जगदीश जोशी : केंद्रीय सरकार छोटी नदी नालों पर वरसाती पानी रोकने के लिये ऋण प्रोग्राम त्वरित कार्य के रूप में और सामूहिक रूप में कब तक शुरू करने जा रही है ?

श्री के० सी० पन्त : यह भी कार्यक्रम है कि छोटे छोटे नालों को रोक कर जहां सिंचाई हो सकती है की जाएगी।

श्री जगदीश जोशी : आपके प्लान में उसका कितना कवरेज है, क्या उसका प्रपोर्शन है ?

श्री के० सी० पन्त : इसमें माइनर सरफेस वाटर से —जहां टोटल सरफेस वाटर का अभी आपने स्टेटमेंट में देखा होगा 241 हजार—वहां माइनर सर ेस वाटर से 45,000 मिलियन क्यूबिक मीटर्स का इंतज़ाम हो चुका है 1973-74 में 96 हज़ार मिलियन क्यू० मीटर ग्राउण्ड वाटर से।

श्री गुणानन्द ठाकुर : सभापति जी, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। जब तक इस देश में पानी की उपयोगिता कृषि काम के लिये या विद्युत के लिये सही ढंग से नही होगी और पूरा पूरा नही होगा, तब तक कृषि के सम्बन्ध में और विद्युत सम्बन्ध में उन्नति नहीं कर सकते हैं। इस सन्दर्भ में मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जब बाढ़ का समय आता है—बाढ़ क्यों आती है, जब कि वर्षा काफी हो जाती है और खासकर हमारे उत्तरी बिहार में जितनी नदियां है उनमें हमेशा बाढ़ आती रहती है जब काफी वर्षा हो जाती है। इस बाढ़ के पानी का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करने के लिये कृषि कार्यक्रम, विद्युत कार्य क्रम और पावर कार्याक्रम क्या क्या बनाये गये है। और कितना प्रतिशत पानी अभी इसका उपयोग किया जाता है। हम कितना पानी रोककर इसका कैनलाइज कर सकते हैं। क्या इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई देशव्यापी योजना बनाई है या बनाने का विचार रखती है ?

श्री के० सी० पन्त : सभापति महोदय, कृषि के लिये सिंचाई का महत्व कितना है, यह बात सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं और इस सम्बन्ध में सरकार की यह नीति रही है कि जितनी जल्दी हो सके सिंचाई साधनों का विकास किया जाय। जहां तक उत्तर बिहार का प्रश्न है, जहां पर नदियों में बाढ़ आती है उसमें एक बड़ी समस्या यह है कि जब गंगा नैपाल से नीचे आती है तो उसके बाद परा मैदान है और इस के बाद कहीं पर भी गुंजायश नहीं है कि कोई बांध बनाया जा सक। अगर गुंजायश है तो वह नैपाल में या उत्तर प्रदेश में गंगा जी में इन नदियों को किस तरह से बांधा जाय, इस बारे में कभी कभी हिन्दुस्तान और नैपाल के बीच में बातचीत होती है। इस दिशा में गंढ़क और कोसी में कछ काम भी शुरू हो चुका है। इसके अलावा कोई आसान तरीका इन नदियों के बांधने का नहीं है और यही बड़ी समस्या हमारे सामने हैं। जहां तक देशव्यापी कार्यक्रम का

सम्बन्ध है, जितनी भी स्कीमें है वे देशव्यापी है। देश के कोने कोने में जितनी भी योजनाए बनाई गई है, चाहे वे मेजर हो, मीडियम हो या माइनर हो, वे सब देशव्यापी है।

श्री भैरो सिंह शेखावत : क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिस पानी का सिंचाई कार्यों में उपयोग किया जाता है, उसमें से कितनी योजनाएं इस प्रकार की है सींचाई के सम्बध में, जो इस समय सिंचाई मंत्रालय, योजना आयोग और सी० पी० डब्लू० डी० के विचाराधीन कई वर्षो से पड़ी हुई हैं ? अगर ये सारी योजनाएं पूरी हो जाएं तो फिर कितना पानी का उपयोग किया जा सकता है ?

श्री के० सी० पन्त : मेजर और मीडियम, जितनी भी योजनाएं है, वे सिंचाई मंत्रायल में हैं। जो माइनर इरीगेशन की स्कीमें है, वे एग्रिकलचर मिनिस्ट्री के मातहत हैं। मेजर और मीडियम स्कीमें जितनी इस वक्त है, अगर वे पूरी हो जाएं, तो उनके द्वारा 31.6 मिलियन हैक्टर एरिया इरीगेट हो सकेगी।

श्री भैरो सिंह शेखावत : आप इस बारे में आंकड़े बतलाइये।

श्री के० सी० पन्त : 1951 में 97 मेजर और 513 मीडियम योजनाएं चौथी योजना के अन्त तक स्थापित की गई थी। इसमें से 22 मेजर और 339 मीडियम योजनाएं समाप्त हो गई है। 75 मेजर और 155 मीडियम योजनाएं जो पहिले से चली आ रही है, पांचवी योजना में चल रही है। एक हजार दो सौ करोड़ रुपये के करीब राशि पांचवी योजना में इस काम के लिये रखी गई है। एक हजार साठ करोड़ रुपया नई मीडियम और मेजर स्कीमों क लिये रखा गया है। इसकी संख्या कितनी है, इस वक्त मेरे पास सूचना नहीं है।

SHRI JANARDHANA REDDY: Sir as per the statement laid on the Table the Minister said, "Some of the important steps being taken for maximising the utilisation of rain water are implementation of larger programmes of major and medium irrigation schemes". May I know from the honourable Minister the steps the Ministry has taken to assist the Andhra Pradesh Government to implement major irrigation schemes like Nagar Junasagar, Pochampad and take up Somasila Project? May I also know from the Minister as to what has happened to the proposal submitted by Dr. K. L. Rao about linking up the Ganges with Cauvery?

SHRI K. C. PANT: So far as specific projects in States are concerned, irrigation is in the State sector and irrigation projects are implemented by the States. . .

DR. K. MATHEW KURIAN: The question has to be answered in posterity.

SHRI K. C. PANT: The Centre helps in two ways. One is that they scrutinise the project report and ultimately approve of the project report and the project. Secondly it gives assistance by way of block loan or grant to the States and part of this is used by them for these projects. These are the two ways and within the State Plan, the States allot money to the various projects. Even this year the Planning Commission has made allocation to the State of Andhra Pradesh for its projects. I know that the State of Andhra Pradesh would like some more money to be given to some of their projects. I also share that view personally. But the hon. Minister is aware of the tight resource position and one cannot ignore this position this year. So far as Ganga-Cauvery link is concerned, the proposal is in the conceptual stage.

DR. Z. A. AHMAD: The hon. Minister has stated that all water comes from the same source. I want to ask one question about the use of sub-soil water. He is aware of the fact that sub-soil water is a tremendous potential source of irrigation. I would like to know what steps are being taken in order to develop and properly tap the sub-soil water through construction of a network of tubewells, particularly in those areas where sub-soil water is easily available.

SHRI K. C. PANT: The question of subsoil water and tapping of that water through tube-wells and surface wells is handled by the Ministry of Agriculture as I indicated earlier. Irrigation is divided between the Ministry of Irrigation and Power and Ministry of Agriculture. I think there is some logic behind it and at present it is divided like that. What is necessary is to see that there is conjunctive use of surface water and ground water and this has become increasingly necessary because in the next 25 years all our surface irrigation water will be utilised and so also our ground water. Though today there is so much of water and there are floods and other problems, in another 25 years we will be exhausting this and we will be able to irrigate only about 50 per cent of the crop area then available. Therefore, the question of conjunctive use of ground water and surface water digging of tube-wells and proper scientific projections of the proper manner of development, in my view, are priority areas.

DR. Z. A. AHMAD: Is there co-ordination between the two Ministries?

SHRI K. C. PANT: Yes.

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : श्रीमन्, देश के ज्यादातर हिस्से में कुओं से आबपाशी होती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए किसानों की सुविधा के लिहाज से मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या अन्डरग्राउन्ड वाटर का सर्वे इस उद्देश्य से कि कितनी गहराई पर पानी आबपाशी के लायक उपलब्ध हो सकता है पूरा हो चुका है और सर्वे रिपोर्ट प्रान्तीय शासन को दी जा चुकी है ?

श्री के० सी० पन्त : अभी सिस्टेमेटिक एसेसमेंट इसका पूरा नही हुआ है। ऐसेसमेंट आजकल किया जा रहा है, सिस्टेमेटिक स्टडी की जा रही है। यह काफी मुश्किल काम है। इसमें होल वगैरह रिग करना पड़ता है। सेटेलाइट्स से जो तस्वीरें आई हैं उनसे भी एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री ने इस दिशा में कुछ काम किया है, उससे भी सहूलियत हो जाती है। वैसे मोटा हिसाब सेन्ट्रल वाटर एंड पावर कमीशन ने यह लगाया है कि जो वारिश होती है उससे ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज 370 हजार मिलियन क्यूबिक मीटर होता है। और जो कैनाल इनफिल्ट्रेशन से रिचार्ज है, जो कैनाल से पानी जमीन मे चला जाता है वह 54 हजार मिलियन क्यूबिक मीटर है। तो इस तरह से यह कुल 424 हजार मिलियन क्यूबिक मीटर है।

श्री ओउम् प्रकाश त्यागी : मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान एक समाचार की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं जो कि एक अमरीकन एक्सपर्ट ने प्रकाशित किया है कि सन् 2000 में भारतवर्ष में पानी का दुर्भिक्ष पड़ेगा। क्या इस पर सरकार ने कुछ विचार किया है कि इस में कहां तक सत्यता है या गंभीरता से इस का मुकाबला करने के लिये सरकार ने कोई विचार किया है ?

श्री के० सी० पन्त : अमरीकन एक्सपर्ट का तो मुझे ध्यान नही है लेकिन एक अखबार में एक स्टेडी निकली थी और एक कोई चतुर्वेदी साहब हैं उन्होंने ने भी मुझे पत्र दिया था जिस के बारे में वक्तव्य था और यहा एक सेमीनार हुआ था जिस में मै गया था। उस में उन्होंने इस ओर ध्यान दिलाया था, और मैं ने भी आप से पहले कहा कि 25 साल में हम सारे सरफेस वाटर का और ग्राउन्ड वाटर का उपयोग कर लेंगे इस की हम को उम्मीद है और इस में 20 हजार करोड़ रुपया मेजर और मीडियम प्रोजेक्ट्स के लिये ही चाहिये। लेकिन जैसे जैसे कृषि की आवश्यकतायें बढ़ेंगी उस के हिसाब से सिचाई की योजनायें भी फैलानी पड़ेगीं। तो 25 साल में यह हो जायगा। तो यह देखना पड़ेगा। इस लिये प्रश्न के पहले ही उत्तर में मैं ने कहा कि अब समय आ गया है कि जब एक साइंटिफिक तरीके से पानी का कैसे उपयोग किया जाय, ठीक से ठीक उपयोग कैसे उस का हो इस के साथ ही हम उस की बचत करने की बात भी सोचें और कैसे इस का एक कोआर्डिनेटेड व्यू लें ताकि

इंडस्ट्री के लिये पानी कितना चाहिये और शहरों के लिये कितना चाहिये इस का निर्धारण हो सके। तो आगे के लिये फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग की बात है और मैं समझता हूं कि यह बहुत जरूरी है।

श्री महावीर त्यागी : इस सवाल पर कितने घंटे लगेंगे ?

श्री सभापति : इरिगेशन का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है इस लिये इस को और सवालों से ज्यादा टाइम देना जरूरी है।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि पानी के विवाद इंटर स्टेट्स के, स्टेट्स के बीच में कितने पड़े हैं, और वह कितने सालों से चल रहे हैं और उन विवादों का फैसला न होने के कारण अभी तक इरिगेशन का कितना नुकसान हुआ है ?

श्री के० सी० पन्त : मैं समझता हूं कि जो मुख्य विवाद है उन में एक तो कृष्ण का है जिस पर ट्राइब्यूनल ने एवार्ड दे दिया है। एक गोदावरी का है जो कि ट्राइब्यूनल के सामने है। एक कावेरी का है जिस के बारे में राज्यों में बात चीत चल रही है। एक नर्मदा का है जो कि ट्राइब्यूनल के सामने फिर चला गया और पंजाब हरियाणा के बीच में भी पानी का बंटवारा करना है जिस पर हम विचार कर रहे हैं। बानसागर वाले का भी कमीशन बन रहा है। जहां तक दूसरा प्रश्न है कि इस से कितने पानी के उपयोग में कमी हुई, यह जरूर है कि इन के तय होने से कुछ क्षेत्रों में पानी का उपयोग कुछ बढ़ जाता लेकिन कुल जितना पानी मिलता है सिंचाई के लिए अगर इस से अधिक भी पैसा मिलता तो वह और जगह इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन यह कहना कि इन की वजह से पानी का सिंचाई के लिए कम उपयोग हुआ, ऐसा मै नहीं मानता।

MR. CHAIRMAN: Yes, Mr. Dhulap. Last question, please.

SHRI K. N. DHULAP: Sir, I have been wanting to put a question on this for long. I am referring to parts (iii) and (iv) of the answer. . .

श्री राजनारायण : और भी सवाल हैं।

श्री सभापति : हम हर एक मेम्बर को कई कई बार नहीं बुला सकते।

We have taken more than twenty minutes on one question.

श्री राजनारायण : मैं किसान का बेटा हूं, खेती करता हूं, मै पानी पाता नही और पानी कहीं और चला जाता है।

श्री सभापति : आप बैठ जाइये।

SHRI VEERENDRA PATIL: Sir, please allow me also. I am also interested in irrigation.

SHRI K. N. DHULAP: Sir, I am referring to replies (iii) and (iv) of parts (b) and (c) of the question. I want to know from the hon. Minister what the percentage of non-irrigation potential is in different States. What steps are being taken by different States for the optimum utilization of the irrigation potential, and within what period they are going to achieve that?

MR. CHAIRMAN: Short question.

SHRI K. N. DHULAP: How much time will be required for modernization?

SHRI K. C. PANT: Sir, I do not have the figures for different States. But broadly the utilization is of the order of 80 per cent—a little more or a little less. This is in respect of major and medium schemes. In respect of minor schemes the utilization is hundred per cent. These are short-term schemes and they are utilized very quickly.

So far as the modernisation and the review of the existing system and improvements in existing irrigation systems are concerned, the fifth Plan document contemplates a comprehensive review of the earlier Plan projects at suitable intervals, comprising teams of specialists, scientists, economists, etc. Such review is expected to reveal several steps that can be taken,

specially in the case of agronomy, water management and operation which enhance the utility of these projects with a modest expenditure. The exact amount which has been earmarked to each State project is not yet available.

Raid in Champaran District for Gold Etc.

*94. SHRI BIPINPAL DAS:
SHRIMATI KUMUDBEN MANISHANKAR JOSHI:
SHRI K. B. CHETTRI:†
DR. V. A. SEYID MUHAMMAD:
SHRI NABIN CHANDRA BURAGOHAIN:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a joint team of Central Bureau of Investigations and Central Excise recently raided the house of one Shri Sitaram Rajhorea in Champaran District in Bihar and recovered huge quantities of gold and documents relating to uranium smuggling; and

(b) if so, what further steps Government have taken in unearthing such cases?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE DEPARTMENT OF PERSONNEL (SHRI RAM NIWAS MIRDHA): (a) A search of the premises of Rajgarhia brothers at Bettiah was carried out by a joint team of the officers of Customs & Central Excise and the Directorate of Revenue Intelligence on 10th June, 1974. Neither any gold nor any document relating to the alleged uranium smuggling was recovered.

(b) Three cases of alleged pilferage of uranium ore are separately under investigation.

SHRI K. B. CHETTRI: Sir, with reference to part (b), may I know from the hon. Minister whether the Government is thinking of sealing all the lockers in the banks in the country simultaneously and then open the same in the presence of the owners of lockers and ask them to account for the gold which may be found in the lockers?

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: Sir, this is actually a question which should be addressed to the Finance Ministry. Part (b) does not concern lockers at all. The question is about uranium smuggling.

SHRI NABIN CHANDRA BURAGOHAIN: May I know from the hon. Minister whether any thefts of uranium have taken place, and what steps have been taken by the Ministry of Home Affairs for the safety and security of uranium in the country?

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: Sir, I have stated in my answer that there are three cases of alleged uranium theft which are under investigation. Two cases are being investigated by the Bihar Police and the third case by the West Bengal Police. As regards the Bihar cases, request has come from the Government of Bihar for CBI take over of investigation of these cases, and the Government of India has accepted their request, and very soon a formal notification will be issued. On 7-4-74 the Bihar Police raided a house in Jamshedpur and recovered 5½ kgs. of a substance suspected to be uranium. It consisted of 750 grams of yellow coloured powder and the rest ash coloured powder, put in several plastic bags. The samples of the seized material were sent to the Atomic Energy Commission Bombay and the Uranium Corporation of India Limited Jaduguda. According to the report received by the police from the UCIL, the sample contained feeble substance of uranium. The report of the Atomic Energy Commission is still awaited.

As regards the other case in Calcutta, the Calcutta Police arrested 5 persons on 25-6-74 and recovered 525 grams of substance suspected to be uranium from them. 3 more were arrested including 2 in Bihar afterwards in connection with a case registered by Calcutta Police. A case has been registered by the Calcutta Police against all the accused persons and investigation is in progress. The material seized in Calcutta was in 5 different packets. 5 samples of seized material were, therefore, sent to the

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri K. B. Chettri.